JOINT FORUM OF NON-EXECUTIVE UNIONS AND ASSOCIATIONS OF BSNL

Date: 01.11.2023

A note on the Wage Revision issue.

Dear comrades,

The Joint Forum has given call to organise district level joint meetings on 02-11-2023, for the purpose of explaining the present status of the Wage Revision issue. The following note may be used by the leaders to explain, the negative role being played by the management and the government and that need to organise, united and powerful struggles.

The Wage Revision of the Non-Executives continues to be in a deadlock. The Joint Forum of the Non-Executive Unions and Associations is spearheading various agitations to break this deadlock prevailing in the Wage Revision. most importantly, a massive dharna programme was organised at Jantar Mantar, New Delhi on 07-07-2023. The unions and associations under the banner of the Joint Forum have mobilised maximum number of employees in these agitations.

Even though, the Joint Forum is taking all out efforts to settle the Wage Revision, the Management continues to remain adamant. The present deadlock in the Wage Revision has arisen due to the unreasonable stand taken by the Management with regards to the new pay scales of the Non-Executives. The new pay scales of the Executives are already recommended by the 3rd Pay Revision Committee (3rd PRC), and it has already been approved by the Government. Whereas, an agreement has to be signed between the Management and the Recognised unions, to finalise the pay scales of the Non-Executives. Accordingly, on 27-07-2018 itself, the new pay scales of the Non-Executives have already been finalised in the Wage Negotiating Committee, through a consensus between the Management Side and the Staff Side.

It is needless to state that, the new pay scales of the Non-Executives are constructed on the basis of the new pay scales of the Executives, as has been recommended by the 3rd PRC. After the retirement of Shri H.C.Pant, Chairman of the Wage Negotiating Committee, Shri R.K.Goyal was appointed as the new Chairman and the Wage Negotiating Committee was also reconstituted. Thereafter, the Management Side went back from it's own commitment on the new pay scales. They argued that, the new pay scales finalised in the Wage Negotiating Committee on 27-07-2018 are very long, which will cause heavy expenditure to the Management, by way of payment of pension contribution to the Government. They proposed a new set of pay scales, by cutting down the minimum and the maximum of the pay scales already finalised in the Wage Negotiating Committee on 27-07-2018.

However, all the efforts taken by the Management Side to cut down the minimum and the maximum of the pay scales of the Non-Executives, which were already finalised in the Wage Negotiating Committee, were rejected by the Recognised Unions on the following grounds:-

(a) The pay scales already finalised in the Wage Negotiating Committee on 27-07-2018 were accepted by the Management Side. After finalising the pay scales through consensus, the Management Side has gone back from it's commitment and is trying to cut down the minimum and the maximum of those pay scales.

(b) The new pay scales proposed by the Management Side are too short. If these pay scales are accepted, the problem of stagnation will come once again.

(c) The pay scales of the Executives are already accepted by the Government. BSNL Management has no power to cut down the minimum or maximum of those pay scales, so as to reduce the expenditure on payment of pension contribution. As such, why the Management wants to cut down the pay scales of the Non-Executives alone?

The 39th of the National Council was held on 07-08-2023. The Recognised Unions raised this issue in the National Council and demanded that the Management should not cut down the pay scales, which are already finalised in the Wage Negotiating Committee on 27.07.2018 itself. However, no solution has come to remove the deadlock.

It is under these circumstances that, the meeting of the Joint Forum has come to the conclusion to explore the option of organising a strike action to settle the Wage Revision issue. The Joint Forum has also decided to organise joint district level meetings on 02.11.2023 and to organise massive human chain programmes on 28-11-2023. The leaders of the Joint Forum at the circle and district levels are requested to effectively mobilise the employees.

Chandeshwar Singh
Chairman

P.Abhimanyu
Convenor

बीएसएनएल के नोन एक्ज़ीक्यूटिव यूनियनों और के एसोसिएशनों का संयुक्त मंच

दिनांक : 01.11.2023.

वेज रिवीजन मुद्दे पर एक नोट

प्रिय साथियों,

वेज रिवीजन मामले की वर्तमान स्थिति समझाने के उद्देश्य से संयुक्त मंच ने दिनांक 02-11-2023 को जिला स्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित करने का आह्वान किया है। प्रबंधन और सरकार द्वारा निभाई जा रही नकारात्मक भूमिका और संगठित, एकजुट और शक्तिशाली संघर्षों की आवश्यकता को समझाने के लिए नेताओं द्वारा निम्नलिखित नोट का उपयोग किया जा सकता है। नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेज रिवीजन पर अब भी गतिरोध बना हुआ है। नोन एक्ज़ीक्यूटिव यूनियनों और एसोसिएशनों का संयुक्त मंच वेतन संशोधन पर गतिरोध को तोड़ने के लिए विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिनांक 07-07-2023 को जंतर-मंतर, नई दिल्ली पर एक विशाल विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संयुक्त मंच के बैनर तले यूनियनों और एसोसिएशनों ने इन आंदोलनों में अधिकतम संख्या में कर्मचारियों को लामबंद किया है। वेज रिवीजन को लेकर संयुक्त मंच भले ही हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रबंधन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वेज रिवीजन में वर्तमान गतिरोध नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेतनमान के संबंध में प्रबंधन द्वारा अपनाए गए अनुचित रुख के कारण उत्पन्न हुआ है। एक्ज़िक्यूटिव्स के नए वेतनमान की सिफारिश तीसरी वेतन संशोधन समिति (तीसरी पीआरसी) द्वारा पहले ही की जा चुकी है, और सरकार द्वारा इसे पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं, नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेतनमान को अंतिम रूप देने के लिए प्रबंधन और मान्यता प्राप्त यूनियनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना है। तदनुसार, नोन एक्ज़िक्यूटिव्स कर्मचारियों के नए वेतनमान को 27-07-2018 को ही प्रबंधन पक्ष और कर्मचारी पक्ष के बीच सर्वसम्मति के माध्यम से वेतन वार्ता समिति में अंतिम रूप दिया जा चुका है। कहने की जरूरत नहीं है, नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के नए वेतनमान को तीसरे पीआरसी द्वारा अनुशंसित एक्ज़िक्यूटिव्स के नए वेतनमान के आधार पर तैयार किया गया है। श्री एच.सी. पंत, वेज नेगोशियेटिंग कमिटी के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के बाद श्री आर.के. गोयल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वेज नेगोशियेटिंग कमिटी का भी पुनर्गठन किया गया। इसके बाद प्रबंधन नये वेतनमान पर अपनी ही प्रतिबद्धता से पीछे हट गया। उन्होंने तर्क दिया कि, 27-07-2018 को वेज नेगोशियेटिंग कमिटी में अंतिम रूप दिया गया नया वेतनमान बहुत लंबा है, जिससे सरकार को पेंशन योगदान के भुगतान के रूप में प्रबंधन को भारी खर्च करना पड़ेगा। उन्होंने 27 07-2018 को वेज नेगोशियेटिंग

कमिटी में पहले से तय वेतनमान के न्यूनतम और अधिकतम में कटौती करके नए वेतनमान का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान को कम करने के लिए प्रबंधन की ओर से किए गए सभी प्रयास, जिन्हें वेतन वार्ता समिति में पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका था, को मान्यता प्राप्त यूनियनों ने निम्नलिखित आधारों पर खारिज कर दिया था :

(A) 27-07-2018 को वेतन वेज नेगोशियेटिंग कमिटी में पहले ही तय किए गए वेतनमान को प्रबंधन पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। सर्वसम्मति से वेतनमान को अंतिम रूप देने के बाद, प्रबंधन पक्ष अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट गया है और उन वेतनमानों के न्यूनतम और अधिकतम में कटौती करने की कोशिश कर रहा है।

(B) प्रबंधन पक्ष द्वारा प्रस्तावित नए वेतनमान बहुत छोटे हैं। यदि ये वेतनमान स्वीकृत हो गए तो एक बार फिर स्थगन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

(C) एक्ज़िक्यूटिव्स का वेतनमान प्रशासन द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। बीएसएनएल प्रबंधन के पास उन वेतनमानों के न्यूनतम या अधिकतम को कम करने का कोई अधिकार नहीं है ताकि पेंशन योगदान के भुगतान पर व्यय को कम किया जा सके। ऐसे में प्रबंधन अकेले नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेतनमान में कटौती क्यों करना चाहता है ? नेशनल काउंसिल की 39वीं बैठक 07-08-2023 को आयोजित की गई। मान्यता प्राप्त यूनियनों ने इस मुद्दे को नेशनल काउंसिल में उठाया और मांग की कि प्रबंधन को वेतनमान में कटौती नहीं करनी चाहिए, जिसे 27.07.2018 को वेज नेगोशियेटिंग कमिटी में अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालाँकि, गतिरोध को दूर करने का कोई समाधान नहीं निकला है। इन परिस्थितियों में, वेज रिवीजन मुद्दे को सुलझाने के लिए हड़ताल की कार्रवाई का विकल्प तलाशने के लिए संयुक्त मंच की बैठक एक निष्कर्ष पर पहुंची है। संयुक्त मंच ने 02.11.2023 को संयुक्त जिला स्तरीय बैठकें और 28-11-2023 को एक विशाल मानव श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। सर्कल एवं जिला स्तर पर संयुक्त मंच के नेताओं से कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से संगठित करने का अनुरोध किया गया है।

चंदेश्वर सिंह पी. अभिमन्यु

अध्यक्ष संयोजक